under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 with effect from 10th December, 1992. Action against VHP is to be taken by the State Governments under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 and other Acts as powers under the Acts are delegated/vested in them.

दिल्ली में भूमि का अतिक्रमण

2882. **श्री चतुरानन मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुरुद्वारा नानकपुरा, नई दिल्ली-110 021 के निकट एक सार्वजनिक कार-पार्किंग स्थल में एक कार-स्कूटर वर्कशाप अनधिकृत रूप से चल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक भवन निर्माण सामग्री सप्लायर ने भी उक्त स्थान पर अवैध कब्जा कर लिया है और वह वहां अपनी भवन निर्माण सामग्री रख रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्थल को खाली कराने के लिए दिल्ली नगर निगम क्या कार्यवाही कर रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नानकपुरा, नई दिल्ली में गुरुद्वारे के निकट सार्वजनिक कार पार्किंग स्थल पर कोई ऑटो वर्क-शाप नहीं चलाई जा रही है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है ।

नानकपुरा दिल्ली में कथित बलात्कार की घटना की सी॰ बी॰ आई॰ जांच

2883. **श्री गया सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नानकपुरा, नई दिल्ली-110 021 की निवासी एक विधवा महिला की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सी॰ बी॰ आई॰ से जांच कराने के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त महिला की 13 वर्षीय स्कूली छात्रा पुत्री का कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अपहरण करने तथा दो लोगों द्वारा 45 दिनों तक प्रतिदिन उसके साथ सामुहिक बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अभियुक्तों में से एक अभियुक्त पुलिस कर्मी है और वह पुलिस मुख्यालय में पुलिस आयुक्त के कार्यालय में तैनात है ;

(घ) क्या सरकार ने थाना रामाकृष्णापुरम के अन्तर्गत आने वाली नानकपुरा पुलिस चौकी के अधिकारियों के विरुद्ध कोताही बरतने, जानबूझ कर बच्ची को मुक्त नहीं कराने तथा बच्ची के दो भाईयों को फर्जी मामलों में फंसाने के आरोपों को गम्भीरता से लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो अभी तक चौकी प्रभारी सहित अन्य सम्बन्धित पुलिस कर्मियों को निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि नानकपुरा, नई दिल्ली, निवासी श्रीमती गोपीदेवी द्वारा दिनांक 31-3-1993 को दायर की गयी एक अपराधिक रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर विशेष अपराध शाखा द्वारा 29-6-93 को एक मामला दर्ज किया गया । उसने याचिका में आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों, जिनके नाम याचिका में दिए गए हैं, ने उसकी 13 वर्षीय पुत्री का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच पड़ताल से यह पता चला कि याचिकाकर्त्ता द्वारा बताए गए तथाकथित अपराधियों के नाम सही नहीं थे । जांच पड़ताल के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो व्यक्तियों, विजय उर्फ बलबीर सिंह और राजू दुग्गल उर्फ राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया, जिनके नाम याचिका में नहीं दिए गए थे ।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उनके द्वारा गिरफ्तार किया गया कोई भी अपराधी पुलिस कार्मिक नहीं है । तथापि बताया जाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित एक अपराधी का भाई, दिल्ली पुलिस में सशस्त्र पुलिस शाखा में उप-निरीक्षक के पद पर कार्य कर रहा है ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच में, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच भी शामिल है ।

Increase in the work done in Government Offices

2884. SHRI BRAHAMDEO ANAND PASWAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of English Typewriters available in the Ministries;

(b) the number of Hindi Typewriters available in the Ministries; and

(c) whether the percentage of work being done in Government Offices has increased over last five years and percentage thereof in each of the five years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) and (b) 11,322 English Typewriters and 2,622 Hindi Typewriters are avail-

able in the Ministries as on 31st Dec. 1992. These do not include Bilingual (Hindi and English) electronic typewriters.

(c) The issue regarding the increase in percentage of work being done in the government offices during the last five years as well as the increase in the percentage thereof, in each of the five years is not a subject matter of the Deptt, of Official Language, Ministry of Home Affairs. Hence, such information is neither collected nor is it available with the Deptt, of Official Language.

2885. *[Transferred to 26th August. 1993.]*

Shifting the CRPF Training Centre situated in Kerala

2886. SHRI O. RAJAGOPAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a proposal is under consideration of the Government to shift the C.R.P.F. Training Centre from Pallippuram near Trivandrum in Kerala State to some other place; if so, the place where it is to be shifted; and

(b) what are the reasons for shifting the Centre?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Increasing Use of Explosives

2887. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government had issued certain directive to the State Government asking them to act on the specific recommendations to stop the increasing use of explosive by the anti-social elements;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) which of the State Governments acting on the Central directive have shown results; and

(d) what is the reaction of the Government with regard to the inaction of the State Governments which ignored the central directive ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) With a view to check the misuse of explosives by anti-social elements, the Central Government had suggested a number of measures to State Government/ UT Administrations. These measures, *inter alia,* require the State Govt./UT Administration to exercise effective control over storage, movement, theft or pilferage of explosives.

(c) and (d) Some State Governments/UT Administrations have confirmed having issued appropriate instructions to the field authorities. There is no information of any State Government/LT" Administration having ignored the measures suggested by the Central Government.

Old Age Pension to War Veterans

2888. SHRI CHATURANAN MISHRA:
SHRI N. E. BALARAM :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether war veterans who are not receiving any pension and who have crossed the age of 65 years are given Rs. 150/- per month old age pension by the Delhi Administration and disbursed through Rajya Sainik Board, Delhi:

(b) whether in a meeting held on 10th November, 1992 and presided by the Lt. Governor of Delhi it was recommended to increese the monthly pension from Rs. 150A to Rs. 300/-;

(c) if so, the details;

(d) reasons for the delay in not approving the recommendation by the Director, Delhi, Ministry of Home Affairs; and

(e) steps being taken to expedite the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (e) In December, 1987 the Government of India had sanctioned a scheme for destitute grant ©Rs. 150/- per month to be paid to the old defence personnel of World War I and II and their widows, who were above 65 and 60 years of age respectively. The income limit for eligibility was Rs. 500A per month. In October, 1992 a proposal was received from Delhi Administration for enhancing the destitute grant from Rs. 150/- per month to Rs. 300/- per month. No final decision has so far been taken in the matter.

2889. *[Trans/erred to 26th August, 1993.]*

पुरानी दिल्ली में रिक्शाओं के चलाये जाने के कारण यातायात अवरुद्ध हो जाना